



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 335] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 1982/श्रावण 20, 1904
No. 335] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 1982/SRAVANA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1982

का. आ. 566(अ)/18-कक/आई डी आर ए/82 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का आ 617(अ)/18-कक/आई डी आर ए/77-तारीख 12 अगस्त, 1977 (जिसे इसमें हमके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक के अधीन मसर्स इन्दोर टेक्सटाइल लिमिटेड, उज्जैन, मध्य प्रदेश नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से आरम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था और उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया था ;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोकीहित में होगा करना समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, 11 फरवरी, 1983 तक छह मास की और अवधि के लिए, मध्य प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन के अधीन बना रहना चाहिए ;

अतः केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 11 फरवरी, 1983 तक, छह मास की और अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगा ।

[फा. सं 3(1) '81-सी. यू. एस.]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 11th August, 1982

S.O. 566(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 617(E)/18AA/IDRA/77 dated the 12th August, 1977 (hereinafter referred to as the said order) the management of the whole of the industrial undertaking known as M/s Indore Textiles Limited, Ujjain, Madhya Pradesh, was taken over under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette, and the Madhya Pradesh State Textile Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Madhya Pradesh State Textile Corporation for a further period of six months upto the 11th February, 1983 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 11th February, 1983.

[File No. 3(1)/81-CUS]

का. आ. 567(अ)/18-ख/आई डी आर ए/82 :—केंद्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-ख की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. 105(अ)/18-ख/आई डी आर. ए./78 तारीख 17 फरवरी, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी सविदाओं, सम्पत्ति, हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आवेशों या अन्य लिखतों (सिवाय उनके जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रत्याभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं) का प्रवृत्तन जिनका सैसर्स इन्दोर टेक्सटाइल लिमिटेड, उज्जैन, मध्य प्रदेश नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो सकते हैं, ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएँ और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि 11 अगस्त, 1982 तक बढ़ा दी गई थी, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है ;

और केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 11 फरवरी, 1983 तक बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-ख की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 11 फरवरी, 1983 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा. सं. 3(1)/81-गी य. एन.]

आर. के. भार्गव, संयुक्त सचिव

S.O. 567(E).—18FB/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 105(F)/18FB/IDRA/78, dated the 17th February, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Indore Textiles Limited, Ujjain, Madhya Pradesh is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from such date and that as the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 11th August, 1982 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 11th February, 1983 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 11th February, 1983.

[File No. 3(1)/81-CUS]

R. K. BHARGAVA, Jt. Secy.